

एक्जिमिअस : निर्यात लाभ



मार्च 2003

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
www.eximbankindia.com पर हमें संपर्क कीजिए

त्रैमासिक प्रकाशन

इस अंक में

- व्यवसाय के अवसर 4
- परियोजना निर्यात पर कार्य बल 6
- सफलता की कहानी : मैट्रिक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड 8
- भारतीय विदेशी क्षेत्र में अद्यतन विकास 9
- कृषि में निर्यात प्रतिस्पर्धा 10
- भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन 12
- प्रमुख समाचार : कैकन, मेक्सिको तक की सैर. विश्व व्यापार संगठन को मंत्री स्तर का पाँचवाँ सम्मेलन 16

2002 के दौरान विदेशी मांग को सुदृढ़ न होने के बावजूद पूरे क्षेत्र में स.दे.उ. वृद्धि के नरम रहने का अनुमान था जो दो प्रमुख कारणों को प्रतिबिंबित करता है (तालिका)। पहले रूस एवं कज़ाकिस्तान में निम्न तेल राजस्व के कारण वृद्धि कम रही जो 2001 के अंत एवं 2002 के प्रारंभ में कमजोर तेल मूल्यों का पिछला प्रभाव प्रतिबिंबित करता है। दूसरे यह कि 2001 में कृषि वृद्धि जो बहुत अधिक थी 2000 से सूखे से राहत के कारण सामान्य स्तर पर वापसी प्रक्षेपित की गई। यद्यपि कुछ देशों के अपवाद के साथ जैसे बेलारूस एवं उज़्बेकिस्तान, स.दे.उ. के अपेक्षाकृत भली भांति घटित रहने की आशा है। साथ ही लैटिन अमेरिका में आर्थिक संकट से सीमित रहा जिसके दोनों क्षेत्रों के बीच निम्न स्तर का व्यापारिक सेतु प्रतिबिंबित होता है।

रूस में ऊर्जा क्षेत्र से होने वाली कम आय के कारण इस क्षेत्र में निवेश में कमी आने और अन्य क्षेत्रों एवं देशों में निवेश बढ़ने की आशा है, हालांकि तेल मूल्यों में हाल की दृढ़ता से इन प्रभावों की कम कर पाने में सहायता मिलेगी। इसके आगे घरेलू मांग के मुख्यतया अत्यधिक निजी खपत एवं सुधारों के साथ हुई प्रगति के कारण आर्थिक गतिविधि में समर्थन बने रहने की आशा है। इन विकासों को प्रतिबिंबित करते हुए वास्तविक सकल देशी उत्पाद के 2002 में 4.4% से बढ़कर 2003 में 4.9% तक दृढ़ होने की आशा है। विदेशी छोर पर ज़बरदस्त घरेलू मांग एवं रूबल में मज़बूती द्वारा चालित स. दे. उ. के

2002 में 7% से घटकर 2003 में 6.3% होने की आशा थी। रूस में धीमी वृद्धि घरेलू मांग एवं वास्तविक विनिमय दर वृद्धि के कारण यूक्रेन में 2002 के 1.7% स. दे. उ. की तुलना में 2003 में इसके 2.6% होने की आशा है।

अन्य देशों जैसे अर्मेनिया, अज़रबैजान, जार्जिया, कज़ाकिस्तान एवं माल्डोवा में वृद्धि के अपेक्षाकृत मज़बूत बने रहने की आशा है जो 2003 में 5 से 7.3% तक रहने की आशा है। जबकि घरेलू मांग के आर्थिक गतिविधि का समर्थक बने रहने की आशा है। इसके विपरीत बेलारूस एवं उज़्बेकिस्तान में अन्य के पीछे रहने की आशा है। इससे व्यापक आर्थिक अस्थिरता, कार्पोरेट पुनर्गठन में कमी तथा प्रतिकूल निवेश वातावरण प्रतिबिंबित होता है। हालांकि तज़ाकिस्तान में कृषि में अत्याधिक वृद्धि एवं औद्योगिक क्षेत्र में संतोषजनक निष्पादन के कारण वृद्धि में मज़बूती बने रहने की आशा है।

सामान्यता पूर्वी यूरोप एवं बाल्टिक क्षेत्र में 2002 के दौरान वृद्धि अपेक्षाकृत अच्छी रही जिसके 2003 में और मज़बूत होने की आशा है। तथापि देशों की आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं अलग होती हैं। पौलैण्ड की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर है, जबकि चेक गणतंत्र हाल में आइ बाढ़ से प्रभावित है जबकि क्षेत्र के अन्य देश कम प्रभावित हुए। इसके अलावा सम्पूर्ण क्षेत्र वैश्विक वित्तीय बाज़ार विकास के प्रभाव से अछूता नहीं है। इन देशों के ईक्विटी मूल्यों में विशेष रूप से

सी आइ एस एवं पूर्वी यूरोप का दृश्य

इस क्षेत्र पर वैश्विक मंदी प्रमाण अपेक्षाकृत नरम रहा रूस एवं यूक्रेन में ज़बरदस्त घरेलू मांग के कारण क्षेत्र का पुनरुत्पादन प्रतिबिंबित करता है। 2001 में सी आइ एस देशों की वास्तविक सकल देशी उत्पाद (स.दे.उ.) वृद्धि 6.3% रही। यद्यपि

कमी आई है। चेक गणतंत्र एवं हंगरी सहित अनेक देशों ने पर्याप्त प्रभावी विनिमय दर संवर्धन का अनुभव भी किया है। मध्य यूरोप एवं बाल्टिक देशों में उभरती हुई अन्य बाजारों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण मजबूत रहा तथा बांड का विस्तार निम्न था इनमें से अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं अपनी चालू खाते के सतत राजकोषीय घाटे के कारण बाजार की संवेदनशीलता के प्रति नाजुक बने रहे। तथापि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि सशक्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह से समर्थित विदेशी वित्तपोषण एवं धारणीय घरेलू मांग के प्रमुख स्रोत उपलब्ध कराते हैं। बाजार के अनुकूल व्यवसाय वातावरण के साथ स्थिर एवं विश्वसनीय व्यापक आर्थिक नीतियों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह को बढ़ाया है। अपेक्षाकृत कम लागत के उत्पादन आधारों के साथ यूरोपीय संघ के बाजारों की बढ़ती पहुँच ने ऐसे अंतर्प्रवाहों के उद्दीपन का कार्य किया है।

एस्टोनिया, लैटविया, एवं लिथुआनिया में मजबूत घरेलू मांग एवं सामान्यतया निम्न मुद्रा स्फीति द्वारा समर्थित 2003 में आर्थिक गतिविधि के दृढ़ होने की आशा है। हालांकि विशाल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह के बावजूद सतत उच्च चालू खाता राजकोषीय घाटा नाजुकता के संभावित स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। एस्टोनिया को सार्वजनिक राजस्व बनाने की आवश्यकता होगी जबकि लैटविया को ऐसी बजट बनाना होगा जो राजकोषीय घाटे में और कमी करने का लक्ष्य बनाए। लिथुआनिया में अनुकूल आर्थिक एवं नीतिगत विकासों को ढांचागत सुधारों से और अधिक समर्थन मिलेगा जो कर प्रणाली को सुधारने एवं देश की विदेशी प्रतिस्पर्धा को सुधारने में लगे हैं।

बुल्गारिया एवं रोमानिया में व्यापक आर्थिक विकास सही दिशा में हैं। यहाँ वृद्धि क्रमशः 2002 में 4.0% से 4.3% एवं 2003 में 5.0% एवं 4.9% बढ़ने की आशा है। तथापि अत्यधिक विदेशी राजकोषीय घाटे के साथ दोनों देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्गठित करने के प्रयास तथा विदेशी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के प्रयासों के साथ स्थिर राजकोषीय व्यवस्था अनुरक्षित करना आवश्यक होगा। बुल्गारिया में लचीलेपन को बढ़ावा एवं व्यवसाय वातावरण सुधार वरीयताएं हैं। रोमानिया में अत्यधिक मुद्रास्फीति जो एक चिंता का विषय है, को व्यापक आर्थिक नीतियों एवं वेतन प्रतिबंध के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है।

पूरे सी आइ एस एवं पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में जहाँ मुद्रास्फीति लगातार घटी है जिससे राजकोषीय समेकन में प्रगति हुई है, रूस एवं ऐसे अनेक देशों में यह चिंता का विषय बना रहा है जैसे बेलारूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं रोमानिया। रूस में लगातार चालू खाता अधिशेष से मैट्रिक विस्तार हुआ है। मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए नकदी को समाहित करने के लिए केन्द्रीय बैंक को तैयार रहने की आवश्यकता है। अन्य देशों में प्रारंभिक रूप से अर्थव्यवस्था में राज्य के सतत हस्तक्षेप द्वारा निर्मित की जाती है जैसे सार्वजनिक उद्यमों को रियायतें, जिससे ऋण एवं मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्र के अनेक देशों में बढ़ती हुई मौद्रिक संवृद्धि के मुद्रास्फीति का प्रभाव उच्चतर मुद्रा मांग द्वारा नरम पड़ा है, साथ ही बार्टर संव्यवहारों में कमी आई है। मध्यावधि में सी आइ एस देशों को प्रमुख चुनौतियाँ सुधार प्रक्रिया को त्वरित करनी होगी विशेषतया संस्थान निर्माण एवं नियंत्रण में। प्रमुख उपायों में शामिल हैं बुनियादी बाजार

संस्थानों की स्थापना, कारक एवं माल बाजार का उदारीकरण, उद्यम पुनर्गठन एवं वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ करना। इस और रूस ने सुधार के नाजुक क्षेत्रों में विशिष्ट प्रगति की है जैसे कर प्रणाली, राजकोषीय प्रबंधन, पेंशन सुधार, श्रम कानून, कृषि भूमि कानून एवं व्यवसाय में प्रशासनिक बाधाएं। जहाँ अन्य सी आइ एस देशों में प्रगति सामान्यतया निम्न है एवं कार्यान्वयन विषम है, रूस में त्वरित सुधार, जो क्षेत्र में प्रमुख भूमिका अदा करता है, इन देशों में भी सुधारों को तेज़ करने में सहायक होगा। क्षेत्र के देश अनेक चुनौतियों का सामना भी करते हैं। विशेषतया अनेक देश प्रारंभिक वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भर है जिससे विदेशी सदमे की नाजुकता बढ़ती है। इसके आलोक में, कज़ाकिस्तान ने राजस्व निर्माण में परिवर्तन से सार्वजनिक व्यय के संवाह रोकने के प्रयास में एक सुदृढ़ीकरण निधि स्थापित की है जबकि कज़ाकिस्तान एवं रूस ने राजस्व में कमी आने के मामले में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए आकस्मिक व्यय योजनाएं बनाई हैं। चूँकि ऐसी निधि/ योजनाओं का परिचालन कठिन साबित होगा। आर्थिक विविधीकरण इन देशों के लिए प्राथमिकता बना रहा। व्यवसाय वातावरण को सुधार के लिए सुधारों कर तेज़ी द्वारा सहज हो सकेगा।

पूर्वी यूरोप के देशों के लिए जहाँ नीतियों को वृद्धि धारित करने की आवश्यकता है, समर्थक ढांचागत सुधारों के साथ राजकोषीय प्रतिबंध अनेक देशों में वरीयता बना रहा। राजकोषीय समेकन एवं प्रतिबंध चालू रहने की आवश्यकता है जो जहाँ सार्वजनिक ऋण के निर्माण को सीमित करता है वह वसूली समर्थन के लिए मौद्रिक नीति को सहज बनाने के लिए संभावना उपलब्ध कराने के रूप में भी कार्य करेगा।

तालिका : सी आई एस एवं पूर्वी यूरोप वास्तविक सकल देशी उत्पाद (स.दे.उ.) वृद्धि उपभोक्ता मूल्य एवं चालू खाता शेष

देश	वास्तविक स.दे.उ. वृद्धि (% परिवर्तन)			उपाभोक्ता मूल्य (% परिवर्तन)			चालू खाता शेष (स.दे.उ. के % के रूप में)		
	2000	2002 प्र	2003 प्र	2000	2002 प्र	2003 प्र	2000	2002 प्र	2003 प्र
सी आई एस	6.3	4.6	4.9	19.9	14.6	4.9	7.5	4.9	4.3
रूस	5.0	4.4	4.9	20.7	15.8	11.0	10.3	7.0	6.3
अर्मेनिया	9.6	7.5	6.0	3.2	2.8	2.8	-7.2	-8.6	-8.2
अज़रबैजान	9.0	7.9	7.3	1.5	2.4	3.3	-1.3	-17.7	-30.4
बेलारूस	4.1	3.5	3.8	61.3	43.1	22.5	-2.2	-1.4	0.5
जार्जिया	4.5	3.5	4.0	4.7	5.9	5.0	-6.7	-6.2	-8.0
कज़ाकिस्तान	13.2	8.0	7.0	8.3	5.8	6.2	-6.9	-3.6	-2.5
किर्गिज गणतंत्र	5.3	4.4	3.8	7.0	4.1	4.5	-3.3	-3.8	-5.4
मोल्डोवा	6.1	4.8	5.0	9.8	6.6	8.4	-7.4	-7.3	-7.7
ताजिकिस्तान	10.2	7.0	6.0	38.6	10.7	7.6	-7.0	-4.2	-4.6
यूक्रेन	9.1	4.8	5.0	12.0	5.1	9.1	3.7	2.6	1.7
उज़्बेकिस्तान	4.5	2.7	3.0	27.2	23.2	13.5	-1.0	-1.1	-0.7
पूर्वी यूरोप									
बल्गारिया	4.0	4.0	5.0	7.5	6.4	4.3	-6.1	-5.6	-5.5
चेक गणतंत्र	3.3	2.7	3.2	4.7	2.7	3.0	-4.6	-5.2	-4.6
एस्टोनिया	5.0	4.5	5.0	5.8	3.7	3.0	-6.1	-6.9	-7.4
हंगरी	3.8	3.5	4.0	9.2	5.5	5.2	-2.2	-3.8	-3.7
लैटविया	7.6	5.0	6.0	2.5	3.0	3.0	-10.0	-8.5	-7.5
लिथुआनिया	5.9	4.4	4.8	1.3	1.1	2.5	-4.8	-5.9	-5.7
पोलैण्ड	1.0	1.0	3.0	5.5	2.1	2.3	-4.0	-3.6	-4.2
रोमानिया	5.3	4.3	4.9	34.5	24.2	19.1	-5.9	-5.1	-4.9
स्लोवाक गणतंत्र	3.3	4.0	3.7	7.3	4.2	7.1	-8.6	-8.5	-7.2
स्लोवेनिया	3.0	2.5	3.2	8.4	7.7	5.5	-0.4	-0.8	-0.6

प्र - प्रक्षेपण

स्रोत - वर्ल्ड ईकोनॉमिक आउटलुक, सितंबर, 2002, अं. मु. को.

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की निजी उद्यम भागीदारी

पहले के सोवियत यूनियन में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के तकनीकी सहायता पक्ष के रूप में 2000 में निर्मित निजी उद्यम भागीदारी है, यह सीधे प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करके, छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यमों को अनुप्राणित करके तथा व्यवसाय के अनुकूल वातावरण निर्मित करके इन देशों में दीर्घावधि आर्थिक वृद्धि की नींव को मज़बूत करना चाहता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भागीदारी ने तदनुसार चार अलग-अलग कार्यक्रम विकसित किये हैं

जैसे आपूर्ति एवं वितरण श्रृंखला निर्मित करना, वित्तीय बाज़ार निर्मित करना, कापोरिट नियंत्रण में सुधार तथा छोटे एवं मध्यम आकार उद्यमों के लिए समर्थन सेवाओं एवं व्यवसाय वातावरण को सुधारना।

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के साथ एक नई व्यवस्था के अंतर्गत एफ़िज़म बैंक अं वि नि के निजी उद्यम भागीदारी के अंतर्गत मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में परियोजनाओं के लिए भारतीय परामर्शकों को समर्थन देगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत एफ़िज़म बैंक द्वारा समर्थित भारतीय परामर्शक निजी उद्यम भागीदारी के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वित्त

निगम द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए अल्पावधि परामर्श कार्य निष्पादित कर सकते हैं।

निजी उद्यम भागीदारी में शामिल देश हैं अर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, किर्गिस्तान, माल्डोवा, रूस, ताजिकिस्तान, यूक्रेन एवं उज़्बेकिस्तान। यह नई पहल अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय विशेषशता की दूरदर्शिता निर्मित करने एवं क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास प्रयासों में मदद के सतत प्रयास का एफ़िज़म बैंक का एक हिस्सा है।

परियोजना अवसर

अद्यतन व्यवसाय अवसर : आने वाली परियोजनाएं

बहुविध निधीयन एजेंसियों द्वारा निधिदत्त जैसे विश्व बैंक (वि.बैं.) एशियाई विकास बैंक (ए.वि.बैं.), अफ्रीकी विकास बैंक (अ.वि.बैं.) एवं यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा निधिदत्त पूरे विश्व में आने वाली परियोजनाओं में भारतीय निर्यातकों के चुनिंदा अवसर एक ओर दिए गए हैं।

व्यवसाय अवसरों के लिए इच्छुक निर्यातक संबंधित निष्पादक एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप हमें सूचित करते रहें तो केन्द्र एक भवन, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, मुंबई में स्थित हमारे समुद्रपारीय बहुपक्षीय निधीयन परियोजना समूह को आपकी सहायता करने में प्रसन्नता होगी। कृपया टेली : 22185272 विस्तार 2301 पर गीता पुरी से संपर्क करें।

देश/ निष्पादक एजेंसी	परियोजना/ संक्षिप्त व्योरा	निधीयन एजेंसी से ऋण
समोआ/ डाक एवं दूरसंचार मंत्रालय, समोआ कम्यू लि., कोषागार विभाग, समोआ सरकार प्राइवेट बैग, एपिआ, समोआ टेली (685) 34324, 22984 फैक्स : (685) 21312, 24779 ई-मेल : hinauri@samoa.ws संपर्क : हिनौरी पेटना वित्त सचिव	दूरसंचार एवं डाक क्षेत्र सुधार परियोजना/ परियोजना का उद्देश्य समोआ के दूर संचार एवं डाक क्षेत्र के निष्पादन में सुधार के लिए इसकी सहायता करना है।	विश्व बैंक 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर
नाइजीरिया/ लागोस महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण (लमाटा) लागोस शहरी परिवहन परियोजना तैयारी कार्यालय (लुटपो) अलासा, पीएमबी 1613, इकेजा नाइजीरिया टेली : (234-1) 773-3780 ई-मेल : lutpo@yahoo.co.uk संपर्क : डॉ. एंथनी मोवेरिओला राज्यपाल के विशेष सहायक	लागोस शहरी परिवहन परियोजना/ परियोजना का उद्देश्य लागोस महानगर क्षेत्र में परिवहन क्षेत्र के प्रबंधन के लिए नाइजीरियाई सरकार की क्षमता को बढ़ाना तथा सार्वजनिक क्षेत्र नेटवर्क की कुशलता को बढ़ाना है।	विश्व बैंक 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर
एफ वाय आर मैकदूनिया/ परिवहन एवं संचार मंत्रालय क्रेवेना स्कोप्का ओप्सिना, 4,100 स्कोप्जे एफ वाय आर मैकदूनिया टेली : (389-2) 145 425 फैक्स : (389-2) 118 144 संपर्क : वास्को पोपोव्स्की	नगरपालिका एवं पर्यावरण कार्रवाई कार्यक्रम / परियोजना का उद्देश्य मैदोनिआ क एजल उपयोगिताओं द्वारा जल एवं खराबजल की बुनियादी सुविधा की निर्माण, पुनर्वसन एवं विस्तार करना है।	यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक 22.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर
अल्बानिया/ ई बी आर संपर्क टेली: (4420) 7338 6534 फैक्स : (4420) 7338 7472 ई-मेल: shaulskk@ebrd.com	सड़क पुनर्निर्माण परियोजना/ परियोजना का उद्देश्य डुरेस वंदागाह एवं एफ वाय आर मैकदोनिआ सीमा के बीच एल्बास-लिब्राहड भाग को सुधारना है जो पूर्वी एवं पश्चिमी कोरिडर का एक भाग है।	यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर
मंगोलिया/ बैंक ऑफ मंगोलिया (सेंट्रल बैंक) कॉमर्स स्ट्रीट - 6, उलानबहार-11 टेली : (976) 322 166 फैक्स : (976-1) 326 252 ई-मेल : junenbat@magicnet.mn श्री उन्नैनबट, गवर्नर	स्वास्थ्य क्षेत्र विकास की दूसरी परियोजना / परियोजना के उद्देश्यों में शामिल है - (i) स्वास्थ्य क्षेत्र परियोजना क अंतर्गत विकसित स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करना (ii) स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना (iii) नाजुक समूहों एवं गरीबों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र की पहुँच एवं उपयोगिता सुधारना	एशियाई विकास बैंक 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर



देश / निष्पादक एजेंसी	परियोजना / संक्षिप्त ब्यौरा	निधीयन एजेंसी से ऋण
लाओ गणतांत्रिक प्रजातंत्र / संचार, परिवहन, डाक एवं निर्माण मंत्रालय विएंटिएन, लाओ पी डी आर टेली : (856-21) 416-322 फैक्स : (856-21) 412-250 संपर्क : श्री खामलौ अट सिडलाकोन, उप मंत्री	छोटे नगर विकास क्षेत्र परियोजना / परियोजना के उद्देश्य हैं (i) शहरी पर्यावरण में सुधार करके, शहरी आवश्यक बुनियादी सुविधा के एवं सेवाओं की उपलब्धता से तथा आजीविका बढ़ाकर छोटे नगर के समुदाय के विशेषतया गरीबों के जीवन स्तर में सुधार, (ii) छोटे नगरों में प्रभावी, प्रतिसादी एवं शहरी बुनियादी सुविधा के धारणीय प्रावधान के लिए विकेंद्रित एवं समर्थित संस्थागत एवं प्रबंधन ढांचे की स्थापना एवं विकास	एशियाई विकास बैंक 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर
ईथियोपिया / जल संसाधन मंत्रालय अदिस अबाबा अफ्रीकी विकास बैंक संपर्क - श्री ए डी म्तेघा निदेशक, देशी परिचालन: अफ्रीकी विकास निधि द्वारा परियोजनाओं का निधीयन किया जाता है।	हरारे जल आपूर्ति एवं स्वास्थ्य परियोजना / परियोजना में शामिल हैं (i) जल आपूर्ति उत्पादन एवं प्रेषण (ii) जल वितरण (iii) स्वास्थ्य (iv) सार्वजनिक शिक्षण (v) हरारे नगर जल आपूर्ति एवं मल निःसारण सेवाओं के लिए संस्थागत समर्थन और (vi) निर्माण पर्यवेक्षण एवं परियोजना लेखा परीक्षा में तकनीकी सहायता	अफ्रीकी विकास बैंक 27.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर
घाना / भूमि एवं वनरोपण मंत्रालय बॉक्स एम 212, अक्रा टेली : (233-21) 665-421 फैक्स : (233-21) 666-801 ई-मेल : guysymes@mlf.africaonline. com.gh संपर्क : श्री जी टेलर्स-लेविस निदेशक, देशी परिचालन : पश्चिम	समुदाय वनरोपण प्रबंधन परियोजना / परियोजना में निम्न घटक होंगे (क) पौधरोपण विकास ; (ख) वैकल्पिक आजीविका समर्थन योजना ; (ग) संस्थागत क्षमता निर्माण और (घ) परियोजना प्रबंधन को सुदृढ़ करना।	अफ्रीकी विकास बैंक 8.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर

अधिनिर्णीत संविदा	
ति माही के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा अर्जित चयनित संविदाएं शपूरजी पालनजी एण्ड कं. लि., मुंबई	आर्थिक विकास के लिए आगाखान निधि द्वारा निधिदत्त अफगानिस्तान में काबूल सेरेना होटल का पुनर्निर्माण
मोहन निर्यात (इंडिया) प्राइवेट लि. नई दिल्ली	विश्व बैंक द्वारा निधिदत्त अफगानिस्तान में प्राप्त आपातकालीन बुनियादी सुविधा पुनर्निर्माण परियोजना के लिए ओवरहेड कंडक्टरों की आपूर्ति की संविदा
पेन्नर इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, हैदराबाद	विश्व बैंक द्वारा निधिदत्त नेपाल में प्राप्त बुनियादी एवं प्रारंभिक शिक्षा परियोजना के लिए ढांचागत स्टील सामग्री एवं फ्रेम की आपूर्ति की संविदा
औरी अवेनिडा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	विश्व बैंक द्वारा निधिदत्त तजाकिस्तान में प्राप्त ग्रामीण बुनियादी सुविधा पुनर्वसन परियोजना के लिए प्रयोगशाला के रसायन रीएजेंट की आपूर्ति की संविदा
सेरम इंस्टीट्यूट आय इंडिया लिमिटेड, पुणे	विश्व बैंक द्वारा निधिदत्त टर्की में प्राप्त स्वास्थ्य परियोजना के लिए चेचक क टीके की आपूर्ति के लिए संविदा
स्ट्राइड्स आर्कोलैब लिमिटेड बैंगलोर	विश्व बैंक द्वारा निधिदत्त यूगाण्डा में प्राप्त एच आइ वी / एड्स नियंत्रण परियोजना के लिए टी बी दवाओं की आपूर्ति के लिए संविदा
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	संयुक्त राष्ट्र के भोजन के लिए अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत इराक में प्राप्त बाजी बिजली स्टेशन परियोजना के लिए टर्न की परियोजना
के ई सी इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन लि., मुंबई	अल्जीरिया में प्राप्त ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए टर्न की संविदा
पेट्रान इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लि. मुंबई	नाइजीरिया में प्राप्त ट्रांसमिशन के लिए टर्न की लाइन परियोजना संविदा
प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन्स लि., हैदराबाद	साऊदी अरब में प्राप्त हाली दम के निर्माण के लिए संविदा

परियोजना निर्यात पर कार्य बल

भारतीय परियोजना निर्यातक परामर्शक आपूर्तिकार एवं सिविल कंस्ट्रक्शन एवं टर्नकी संविदाकारों ने अनेक क्षेत्रों एवं अनेक समुद्रपारीय बाजारों में सफलतापूर्वक परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है। भारतीय कंपनियों ने चुनौती भरे वातावरण में अनेक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की क्षमता दिखाई है। तथापि अपेक्षाकृत केवल थोड़े से ही भारतीय परियोजना निर्यातकों को संविदाएं प्राप्त हुई हैं और वह भी कुछ ही जगहों में।

परियोजना निर्यात से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने एवं ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए जो परियोजना निर्यातों को बढ़ा सके, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा परियोजना निर्यात पर एक कार्य बल गठित किया गया है।

कार्य बल के सदस्य

- श्री जी सी दत्त, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय अध्यक्ष
- वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
- राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- प्रधानमंत्री कार्यालय
- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ
- भारतीय उद्योग संघ
- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
- भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड
- भारतीय निर्यात-आयात बैंक - सचिवालय

यदि भारतीय कंपनियों द्वारा महसूस की जा रही बाधाओं को निम्न द्वारा संबोधित किया जाए तो इस वृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है :

- भारतीय मिशनों द्वारा अधिक सक्रिय भूमिका सहित संवर्धित संस्थागत समर्थन
- अधिक अवधि तक ज्यादा प्रतिस्पर्धी ऋण एवं बीमा की शर्तों की उपलब्धता
- परियोजना निर्यातक के रूप में संवर्धित ब्रांड छवि
- योजना प्रक्रिया के शुरुआती दौर में प्रणोद बाजारों में भारतीय परामर्शकों की संवर्धित उपस्थिति
- उन्नयनकारी तरीके अपनाने वाले उद्योग उद्योग संघ

कार्य बल ने अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों में निम्न शामिल है -

- परियोजना से संबंधित मुद्दों जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है को संबोधित करने के लिए परियोजना निर्यातों पर उच्चस्तरीय स्थायी समिति का गठन करना। यह समिति समय पर एवं पर्याप्त प्रतिसाद सुनिश्चित करने के लिए विशेष छूट एवं कराधान सहित उच्च स्तरीय हस्तक्षेप चाहनेवाले अनेक मुद्दों को हल करेगी ताकि परियोजना निर्यातों को सरल बनाया जा सके समिति के अध्यक्ष, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव होंगे तथा वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, एक्जिम बैंक एवं भारतीय निर्यात ऋण गारंटी लिमिटेड इसके सदस्य होंगे।

□ समन्वयन एजेंसी की स्थापना

एक परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना जो परियोजना निर्यातों को बढ़ाने के लिए शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी। भारतीय मिशनों, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, एक्जिम बैंक, भा.नि.ऋ.गा.नि.लि., उद्योग संघों एवं वाणिज्यिक बैंकों के बीच प्रभावी ऊर्जा निर्मित करने के लिए यह एक स्वायत्तशासी निकाय होगा ताकि परियोजनाओं का शीघ्र पता लगाना सुनिश्चित हो, आसूचना एकत्रित की जा सके, सूचना का प्रभावी प्रसार किया जा सके। इस तरह की एजेंसी स्थापित करने में एक्जिम बैंक की प्रमुख भूमिका होगी।

□ बहुविध एजेंसी द्वारा निधिदत्त परियोजनाओं का लक्ष्य

- विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक जैसी एजेंसियों द्वारा निधिदत्त परियोजनाएं, भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए आकर्षक व्यवसाय अवसर प्रस्तुत करती है। एक रणनीतिक रूप से समन्वयित प्रयास इस आकर्षक प्रखण्ड में संवर्धित हिस्सा प्राप्त करने में भारतीय कंपनियों की संभावना में सुधार ला सकता है।
- भारत को क्षेत्रीय विकास संस्थानों का सदस्य होना चाहिए जैसे अंतर अमेरिकी विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, मध्य अमेरिकी आर्थिक एकीकरण बैंक, वेस्ट इंडीज विकास बैंक, पश्चिम अफ्रीकी विकास बैंक, पी टी ए बैंक।

□ भारतीय मिशनों का क्षमता निर्माण

सक्रिय उपायों के माध्यम से परियोजना निर्यातों के समर्थन के लिए भारतीय मिशनों में परियोजना सरलीकरण कक्ष स्थापित किए जा सकते हैं। सूचना के आदान प्रदान, व्याख्या के माध्यम से बोलियाँ लगाना एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई से अवसरों को पता लगाने एवं हथियाने के उद्देश्य से, कक्ष पी ई पी सी से निकट समन्वय स्थापित करेगा ताकि समय पर प्रभावी हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके।



वर्ष 2001-2002 के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा प्राप्त चुनिंदा संविदाएं	
संविदाएं	देश
टर्नकी संविदाएं रिफाइनरी नष्ट करने की परियोजना ट्रांसमिशन लाइन परियोजना बिजली परियोजनाओं के लिए गैस टर्बाइन जनित्र का निर्माण एवं आपूर्ति एक एआफोर्स बेस परियोजना के लिए विद्युतीय-यांत्रिकीय कार्य क्वीन मेरी शिप के लिए हीटिंग, वेंटिलेशन एवं एअर कंडीशनिंग कार्य टेलीकाम नेटवर्क परियोजना	नीदरलैण्ड ओमान एवं अल्जीरिया इराक एवं आस्ट्रेलिया कतार फ्रांस साऊदी अरब
निर्माण संविदाएं सड़क पुनर्वसन एवं रेल ओवरब्रिज परियोजना स्टील के जलभंडारण टैंक एवं परिवहन परियोजना	बांग्लादेश यू ए ई
आपूर्ति संविदाएं कोटेड स्टील पाइपों का निर्यात फेरो-क्रोम निर्माण उपस्कर स्टेनलेस स्टील स्लैब्स वेल्डेड स्टील पाइप	जर्मनी ईरान अमेरिका नाइजीरिया
परामर्श संविदाएं सीमेंट संयंत्र का परिचालन एवं अनुरक्षण पेट्रोलियम रिफाइनिंग संयंत्र का आधुनिकीकरण पेट्रोकेमिकल कंपनी के लिए प्रबंध संविदा सड़क सुधार एवं अनुरक्षण परियोजना लोकोमोटिव का अनुरक्षण क्षेत्रीय विकास बैंक के निजीकरण का अध्ययन	साऊदी अरब कुवैत ईरान बांग्लादेश मलेशिया युगांडा

सकती है। एक्रिजम बैंक अपने अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से नि वि नि को प्रशासित कर सकता है। नि वि नि ऐसे संव्यवहारों के समर्थन में इस्तेमाल की जाए जो भारत सरकार द्वारा देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के हित में प्राथमिकता के मामले के रूप में आवश्यक समझा जाए।

- निर्यात ऋण में कमी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मध्यावधि दीर्घावधि आधार पर बैंक दर पर एक्रिजम बैंक में जमा किया जाए। एक्रिजम बैंक इन रूपए की निधि को भारत सरकार के साथ डॉलर संसाधन के लिए बदले।
- भारि बैं द्वारा घटित विदेशी मुद्रा रिज़र्व भी इस उद्देश्य के लिए संघटित किया जाए।
- एक्रिजम बैंक का ईक्विटी आधार सुदृढ़ किया जाए।
- भारत सरकार ब्याज समता योजना द्वारा एक्रिजम बैंक का समर्थन करे।
- भारत सरकार के एक एजेन्ट के रूप में एक्रिजम बैंक समुद्रपारीय सरकारों के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण-व्यवस्था का परिचालन करे। इससे परियोजना निर्यातों के समर्थन एवं भारत सरकार के उद्देश्यों के लिए एक्रिजम बैंक के चालू परिचालनों के बीच ऊर्जा निर्मित होगी।

विचारार्थ विषय

- ❖ भारत के परियोजना निर्यात के निष्पादन का विश्लेषण
- ❖ मुद्दों/बाधाओं की पहचान
- ❖ अंतरराष्ट्रीय चलनों के विरुद्ध बेंचमार्किंग
 - निर्यात ऋण एजेंसियों
 - व्यापार संवर्धन एजेंसियों
- ❖ परियोजना निर्यातों में मात्रात्मक वृद्धि प्राप्त करने के लिए सिफारिशों
 - नीति
 - क्रियाविधि
 - संस्थान
- ❖ सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा
 - अल्पावधि
 - मध्यावधि
 - दीर्घावधि

□ भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (भा नि ऋ गा नि) को सुदृढ़ करना

- सरकार द्वारा भा नि ऋ गा नि को सेवा उपलब्ध कराने के लिए इसी तरह समर्थन देना चाहिए जैसे प्रतिस्पर्धी देश में परियोजना निर्यातक अपने निर्यात ऋण बीमाकर्ता से प्राप्त करता हो।
- भा नि ऋ गा नि का ईक्विटी आधार सुदृढ़ करना
- बिना पुनर्बीमा की आवश्यकता के उच्च मूल्य के परियोजना जोखिमों को कवर करने के लिए भा नि ऋ गा नि का सक्षम बनाने के लिए समर्थन
- पुनर्बीमा के न रहते भा नि ऋ गा नि सरकार के राष्ट्रीय हित खाते से समर्थन लेने की स्थिति में होना चाहिए या सरकार की ओर

कवर परिचालित करने की स्थिति में होना चाहिए।

- जोखिमों का निम्नांकन सरकार के खाते एवं सरकार की ओर से किया जा सकता है।
- जैसा कि यू के, आस्ट्रेलिया, कोरिया गणतंत्र जैसे अन्य देशों में अभिभावी है राष्ट्रीय हित के खाते के संबंध में किए गए प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- एक्रिजम बैंक को सुदृढ़ करना
 एक्रिजम बैंक को अगले 6 वर्षों तक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की निधि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाए ताकि बड़े मूल्य की परियोजनाओं को अधिक प्रतिस्पर्धी ऋण शर्तों तथा लंबी वापसी अवधि के लिए यह समर्थन दे सके। इसे कार्यान्वित करने के लिए निर्यात विकास निधि वाहन का कार्य कर

मैट्रिक्स लेबोरेटरीज़ लिमिटेड की सफलता की कहानी

पहले हेरेन ड्रग्स एण्ड फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के नाम से जाने जानी वाली मैट्रिक्स लेबोरेटरीज़ लिमिटेड सिकंदराबाद सक्रिय फॉर्मास्यूटिकल्स तत्वों को बनाने में लगी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 1984 में स्थापित यह इवुप्रोफेन एवं निमेसुलाइट जैसे कम मूल्य के अधिक मात्रा में थोक दवाइयों का निर्माण करती थी। कंपनी की उत्पाद रूपरेखा में निम्न प्रौद्योगिक एवं कम मार्जिन देख गया है। मई 2000 में एम एल एल के प्रबंधन में बदलाव आया और कंपनी के भाग्य फिर गई। श्री एन. प्रसाद एवं श्री एम. रविंदर के नेतृत्व वाले प्रबंधन ने कंपनी के कम मूल्य के उच्च आयतन उत्पाद को बदलकर उच्च मूल्य के कम आयतन की थोक दवाइयों में बदल दिया। काक्स -2 बाधक एवं एंटी एड्स एवं एंटी डिप्रेसेन्ट्स जैसी मूल्य वर्धित दवाओं पर जोर दिया गया। एम एल एल के प्रबंधन मण्डल में श्री एन प्रसाद, अध्यक्ष के नेतृत्व में उद्योग के ऐसे टेक्नोक्रेट एवं व्यावसायिक हैं जिनके पास व्यापक अनुभव है। एम एल एल ने विनियमित से अर्धविनियमित बाजारों में भी अपना ध्यान लगाया है। एम एल एल की निर्माण सुविधाएं आंध्रप्रदेश के जी डिमेटला एवं काजिपल्ली में स्थित है।

एम एल एल सिटालोप्राम नामक एंटी डिप्रेसेंट

दावा अल्फ्रेड ई टिफेनवैचर जर्मनी को आपूर्ति करनेवाली एक मात्र भारतीय कंपनी है बदले में ए ई टी बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों फार्मा कंपनियों को ब्लक सक्रिय तत्व आपूर्ति करता है। डेन्मार्क का लुंडबैक अमेरिकी बाजार में सिटालोप्राम का वर्तमान पेटेंट धारक है तथा उत्पाद के लिए अनेक प्रक्रियाओं को पेटेंट किया है। तथापि एम एल एल ने उत्पाद के लिए एक अनोखी गैर उल्लंघनकारी प्रक्रिया विकसित करने में सफल रही है। यूरोपीय बाजार में विशुद्ध एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से लुंडबैक ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में से सिटालोप्राम को हटाने के लिए एम एल एल को एक ऑफर दिया जो एम एल एल द्वारा उत्पाद के दीर्घावधि सामर्थ्य एवं यूरोप में जातिगत फॉर्मास्यूटिकल कंपनियों के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। एम एल एल के उत्पाद रूपरेखा में अन्य उच्च मार्जिन उत्पाद शामिल है जैसे नेविरापाइन (एंटी एड्स), मोंटे लुकास्ट (एंटी अस्थमा), नेलफिनाविर (एंटी वायरल) एवं गेटिफ्लोक्सासिन (एंटी बायोटिक)। एम एल एल ने एंटी-डिप्रेसेंट औषधियों के निर्माण के लिए एक संपूर्ण उत्पादन ब्लाक समर्थित किया है। एंटी डिप्रेसेंट बाजार इस समय 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंका गया है तथा 2005 तक इसके 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ने की आशा है। पिछले 3 वर्षों में एम एल एल ने प्रभावी वृद्धि रिकार्ड की है। 1999-2000 में 39 करोड़ रुपये से सी ए जी आर का 62% बढ़कर 2001-02 में 102 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने 1999-2000 के दौरान 9 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में 2001-2002 में 7 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ रिकार्ड किया। इससे मई 2000 से कंपनी के प्रबंधन में हुए प्रबंधन का अनुकूल प्रभाव प्रतिबिंबित होता है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का निर्यात 0.50 करोड़ रुपए से बढ़कर 21 करोड़ रुपये हो गया। एम एल एल के निर्यात में जर्मनी में सर्वाधिक निर्यात के साथ 35 से अधिक देश शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31/12/2002 को समाप्त 9 महीनों की अवधि में एम एल एल ने अपने परिचालन स्तर में

मात्रात्मक वृद्धि प्राप्त की है। इसने 184 करोड़ का आवर्त रिकार्ड किया है, 136 करोड़ रुपये का निर्यात रिकार्ड किया है तथा 77 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। परिचालनात्मक, वित्तीय एवं विपणन ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से एम एल एल ने मेडिकॉर्प टेक्नालॉजीज़ लि. एवं वॉरिन लेबोरेटरीज़ लि. को एम एल एल के विलय करने की योजना बनायी है। मेडिकॉर्प टेक्नोलॉजीज़ लि. एवं वॉरिन लेबोरेटरीज़ लिमिटेड, एक आई एस ओ 9001 प्रमाणित कंपनी है। इसने जी एम बी (डब्ल्यू एच ओ), एम सी ए (यू के), टी जी ए (आस्ट्रेलिया) एवं यू एस एफ डी ए सहित विभिन्न गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त किया है। वॉरिन लेबोरेटरीज़ की निर्माण सुविधा आई एस ओ 9002 द्वारा प्रमाणित एवं जी एम पी (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तावित विलय से उच्च मूल्य निम्न आयतन उत्पादों, विश्व स्तर का उत्पादन एवं अनुसंधान तथा विकास सुविधाएं, ग्राहकों का व्यापक आधार, लागत अनुकूल प्रक्रियाओं का विकास एवं उन्नयन करने वाली कंपनियों के साथ निर्माण संविदा का गठबंधन करने में कंपनी को सुविधा मिलेगी। अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारने की दृष्टि से एम एल एल ने जीडीमेटला में अपनी मौजूदा सुविधाओं पर 18 करोड़ रुपये की लागत का विस्तार कम आधुनिकीकरण परियोजना शुरू की है जो एक्जिम बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए 12 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के रूप में आंशिक रूप से वित्तपोषित है। एक्जिम बैंक से समय से वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराए जानेकी वजह से कंपनी ने लागत में बिना किसी वृद्धि के रिकार्ड समय में यह परियोजना पूरी की। इस परियोजना से निर्यात सहित कंपनी को अपना आवर्त बढ़ाने में मदद मिलेगी।

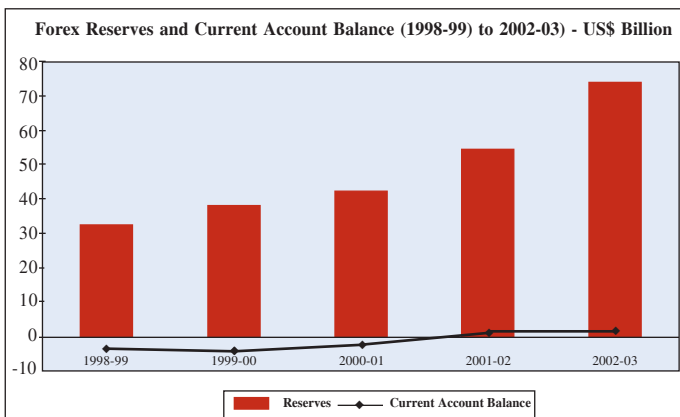
कंपनी ने जीडीमेटला एवं पाशामालासम में मेडिकॉर्प की इकाई में सुविधाओं को और बढ़ाने के अलावा काजीपल्ली में अपनी सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन की योजना बनाई है।

भारत के विदेशी क्षेत्र में हाल के विकास

भारत के विदेशी क्षेत्र में अनुकूल विकास हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुखताएं हैं। ये विकास अन्य बातों के साथ-साथ विदेश व्यापार में प्रोत्कर्ष, चालू खाते में अधिशेष एवं विदेशी मुद्रा भण्डार के विशिष्ट निर्माण से घिरे होंगे।

वैश्विक आर्थिक सुधार प्रतिबिंबित करते हुए, यद्यपि शुरू में जिसकी आशा थी उससे कम, वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि की आशा की गई तथा घरेलू निर्माण क्षेत्र में सुधार की आशा की गई पिछले वर्ष में कमी के बाद वर्ष 2002-03 के दौरान भारत के निर्यातों में अत्यधिक वृद्धि हुई।

अप्रैल-जनवरी 2002-03 के दौरान वाणिज्यिक निर्यातों में 17.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 35-92 बिलियन अ.डॉ. से बढ़कर 42.17 बिलियन अ.डॉ. थी। साथ ही सॉफ्टवेयर निर्यात जो वाणिज्यिकी निर्यातों में शामिल नहीं थे 2001-02 में 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2002-03 में 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए। निर्यात निष्पादन में अंतर्निहित उत्पादकता हीरे जवाहरात, कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों, अनाजों, इंजीनियरी के सामानों रसायन एवं संबंधित उत्पादों, अयस्कों एवं



Figures for 2002-03 : Current Account Balance — April-September 2002; Forex Reserves - as on March 14, 2003.

खनिजों एवं चमड़ा एवं उससे बनी वस्तुओं के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

आयातों का जहाँ तक सवाल है, निर्माण गतिविधि में सुधार प्रतिबिंबित होता है। अप्रैल-जनवरी 2002-03 में गैर तेल आयातों में 13.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बढ़कर 34.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जबकि तेल आयात 22.02 प्रतिशत बढ़कर 14.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए। यह वृद्धि खास कर कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल-जनवरी 2002-03 में सम्पूर्ण आयातों में 15.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 42.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 49.34 बिलियन अ.डॉ. हो गया। मोतियों, हीरे जवाहरातों, पूंजीगत सामानों, इलेक्ट्रॉनिक सामानों एवं खाद्य तेलों के आयातों में अत्याधिक वृद्धि से वर्ष के दौरान गैर तेल आयातों में वृद्धि हुई। प्रारंभिक रूप से संवर्धित निजी स्थानांतरणों (प्रेषणों एवं) सॉफ्टवेयर निर्यात वृद्धि के कारण अदृश्य प्रवाह में अल्पावश्यकता से चालू खाते शेष में बढ़ोत्तरी हुई है जो 24 वर्षों के अंतराल पर 2001-02 में 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर या सकल देशी उत्पाद का 0.3 प्रतिशत है। अप्रैल-सितंबर 2002 के दौरान चालू खाते में 1.67 बिलियन अ.डॉ. का अधिशेष 2002-03 के दौरान सतत सशक्त अदृश्य प्रवाह के कारण हुआ।

चालू खाते में अधिशेष प्रतिबिंबित करते हुए गैर ऋण निर्माण करने वाले अंतर्प्रवाह एवं मूल्यांकन लाभ से भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में 2001-02 से विशेष वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप भारत का कुल विदेशी मुद्रा भण्डार 2001 में 42.28 मिलियन अ.डॉ. की तुलना में 2002 के मार्च के अंत में 54.11 अ.डॉ. हो गया तथा 14 मार्च 2003 को 73.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्तमान भण्डार स्तर एक वर्ष से अधिक के आयातों के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त होगा।

भारतीय निर्यातों की संव्यवहार लागत : एक समीक्षा पर एक्जिम बैंक का अध्ययन

भारतीय निर्यातों की संव्यवहार लागत : एक समीक्षा पर एक्जिम बैंक का कार्यकारी दस्तावेज़ भारत के निर्यातों में संव्यवहार लागतों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है, जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी विभिन्न क्रियाविधिक जटिलताओं वित्तपोषण एवं संव्यवहार समस्याओं की उपलब्धता से उत्पन्न हों। भारत के निर्यातों की संव्यवहार लागतों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय निर्यातों की संव्यवहार लागत: एक विश्लेषण पर एक्जिम बैंक ने 1998 में एक अध्ययन किया था जिस से 1999 में भारतीय निर्यातों की संव्यवहार लागत पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी।

1998 में किए अध्ययन का अद्यतन वर्तमान अध्ययन 82 फर्मों के नमूना सर्वेक्षण पर आधारित है जो अधिकांशतः 10 क्षेत्रों में फैली अधिकांशतः छोटी एवं मध्यम आकार फर्में थीं। चुने हुए प्रत्येक क्षेत्र में निर्यातकों की अनुभूति पर आधारित संव्यवहार लागतों को निर्यात राजस्व के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है जो बदले में ऐसी संव्यवहार लागतों की उपस्थिति के कारण न मिलने वाला राजस्व प्रतिबिंबित होता है। अध्ययन ने 2002 में सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष करों पर गठित कार्य बल के लिए निविष्टि के रूप में कार्य किया। अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि संव्यवहार लागत घटी है, यद्यपि वे कतिपय क्षेत्रों विशेषतया वस्त्र/कपड़े एवं फॉर्मस्यूटिकल्स में विशिष्ट लागत लगाता रहा। वस्त्र, कपड़ा क्षेत्र में पहले के 15% के अनुमान की तुलना में निर्यात राजस्व का 3.8% रहा जबकि फॉर्मस्यूटिकल क्षेत्र में पहले के अनुमानित 10 प्रतिशत की तुलना में निर्यात राजस्व का लगभग 8% रहा, यह निर्यातकों के लिए विभिन्न लागतों की वापसी मिलने में विलंब के कारण था। इंजीनियरी सामानों, रसायनों, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं कृषि उद्योगों के मामलों में भी संव्यवहार लागतों में कमी आई है।

कृषि में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता

अकुशलता को दूर करके स्थिर लाभों के मूल्यांकन के लिए सामान्य संतुलन माडल का इस्तेमाल किया है कृषि में बहुविध उदारीकरण वैश्विक सकल देशी उत्पाद के 0.44% तक कल्याण में बढ़ सकता है। औद्योगिक देशों के लिए आप उनकी सकल देशी उत्पाद के 0.43% तक बढ़ने का अनुमान है जबकि विकसित देशों के लिए वही उनकी सकल देशी उत्पाद का 0.51% तक होने का अनुमान है। नई प्रौद्योगिकियों, उच्चतर निवेशों एवं उच्चतर उत्पादकता वृद्धि के कारण होने वाले संभावित गतिशील लाभों को ध्यान में रखते हुए लाभों में और सुधार किया जा सकता है।

कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराए गए समर्थन की प्रकृति एवं डिग्री पूरे देश में भिन्न है। साधारणतया, समर्थन का लगभग दो तिहाई हिस्सा मूल्य आधारित माना जा सकता है अर्थात् प्रशुल्क एवं निर्यात रियायतों के रूप में। यूरोपीय संघ निर्यात रियायतों का प्रमुख उपयोगकर्ता है जबकि जापान ने उच्च प्रशुल्क के माध्यम से कृषि आयातों पर नियंत्रण रखा है। अमेरिका ने विशेष तया उत्पादन रियायतों पर विश्वास किया है।

विश्व व्यापार संगठन का कृषि पर करार निर्यात रियायत चलनों को सूचीबद्ध किया है जो कृषि क्षेत्र में अभिभावी है। विकसित देशों को 6 वर्षों की अवधि में घटाना अपेक्षित है, रियायती निर्यातों का आधार अवधि आयातन 21% तक एवं तदनु रूप रियायतों का मूल्य 36% तक विकासशील देशों के मामले में यह क्रमशः 14% एवं 24% है, लेकिन 10 वर्षों की अवधि में। करार का विशेष एवं अलग स्वैये का प्रावधान विकासशील देशों को विपणन एवं अंतरराष्ट्रीय परिवहन रियायतें मंजूर करने की भी स्वीकृति देता है। तथापि कृषि करार उच्च आय वाले ओ ई सी डी देशों द्वारा अनुरक्षित व्यापार विदूषक नीतियों को ठीक करने में सफल नहीं रहा है। गेहूँ, अपरिष्कृत अनाज, तिलहन, वनस्पति तेल, शक्कर, डेरी उत्पादों एवं फल तथा सब्जियों विकासशील देशों की प्रमुख उपज है जिनपर

अधिक निर्यात रियायतों जारी हैं। भारत विश्व का दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह खाद्यान्न का, फलों एवं सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पोल्ट्री उत्पादों का पाँचवां सबसे बड़ा उत्पादक है तथा मछली का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। अत्याधिक संसाधनयुक्त होते हुए भारत कृषि व्यापार से लाभ लेने के लिए विशिष्ट संभावना रखता है। तदनुसार भारत कृषि में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए बहुविध स्तर की परिचर्चाओं में प्रखर वक्ता रहा है। विश्व व्यापार संगठन के अनेक सदस्य कुछ विशिष्ट वस्तुओं को लक्ष्य बनाने के उद्देश्यों से वर्षानुवर्ष आधार पर उत्पादों के बीच निर्यात रियायतें लगाते हैं। सदस्य अप्रत्युक्त रियायतों को अगले साल के लिए भी ले जाते हैं जिसका मूल्यों पर संचयी अवसादी असर होता है। जिससे अन्य निर्यातक देशों का प्रतिस्पर्धी लाभ घटता है। भारत ने रियायतों को अगले साल ले जाने की प्रथा को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु तत्काल आवश्यकता व्यक्त की है। भारत ने कृषि करार के निर्यात रियायत कटौती बाध्यताओं के अंतर्गत निर्यात ऋण, गारंटी, मूल्य छूट एवं बीमा कार्यक्रम सहित सभी तरह की आवश्यकता महसूस की है। इसके अलावा भारत ने खाद्य सहायता के प्रावधान में उच्चतर पारदर्शिता के महत्त्व को मान्यता दी है।

वैश्विक कृषि समर्थन का औसत स्तर 1986-88 में 38% से 1999-01 में 31% घटा है। यूरोपीय संघ सामान्य कृषि नीति ने मूल्य आधारित समर्थन के हिस्से को कम करने का प्रस्ताव किया है। इसी तरह अमेरिका में हर तरह की रियायतों समाप्त करने के अभिक्रम है। औद्योगिक देश के कृषि समर्थन के आकार एवं संघटन में ये कटौतियों प्रशंसनीय है तथा कृषि व्यापार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में योगदान करेंगी। तथापि विकासशील देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित देशों को मौजूदा विद्रपता अभिस्वीकृत करने एवं उपचारात्मक उपाय करने में उनके सम्मिलित प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है।

कृषि क्षेत्र विकासशील देशों के सकल देशी उत्पाद के लिए विशिष्ट सहयोग करने वाला है तथा रोज़गार का प्रारंभिक स्रोत है। यद्यपि कृषि वस्तुओं में व्यापार निर्मित वस्तुओं की तुलना में मूल्य के संबंध में कम है फिर भी विकासशील देशों में कृषि निर्यात विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत है। कम एवं मध्यम आय वाले देश वास्तव में उच्च आय वाले ओ ई सी डी देशों के संबंध में खाद्य पदार्थ एवं कृषि के कच्ची सामग्री के शुद्ध निर्यातक है। अत एवं कृषि में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता विकासशील देशों की बेहतर वृद्धि निष्पादन के लिए अनिवार्य है। तथापि कृषि में अंतरराष्ट्रीय व्यापार औद्योगिक देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए उच्च स्तरीय समर्थन उपायों द्वारा निरूपित है। ऊंचे प्रशुल्क, निर्यात, रियायतें, उत्पादन रियायतें एवं प्रत्यक्ष आय समर्थन ये सभी कृषि वस्तुओं के विश्व मूल्यों को कम करने में सहायक हैं तथा विकासशील देशों के हित के विरुद्ध कार्य करते हैं। उच्च डिग्री के समर्थन से उच्चतर निर्यात निर्मित होते हैं तथा जैसे-जैसे विश्व बाज़ार की आपूर्ति बढ़ती है जिससे अधिक उत्पादक गतिविधियों से दूर संसाधन आबंटन होता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अनुमान के अनुसार जिसने विद्रूप कृषि मूल्यों द्वारा होने वाली

एक्जिम बैंक ने ईरान को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सबसे बड़ी ऋण-व्यवस्था उपलब्ध करायी है

भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने ईरान में भारत के निर्यातों के वित्तपोषण के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अब तक की सबसे बड़ी ऋण-व्यवस्था उपलब्ध कराई है। इस करार पर भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं ईरान के राष्ट्रपति श्री एच एस एम खतूनी की उपस्थिति में 25 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में श्री टी सी वेंकटसुब्रमण्यन प्रबंध निदेशक एवं मु का अ. एक्जिम बैंक एवं 7 ईरानी वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये।

ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत ईरानी आयातकों को संविदा मूल्य का 15 प्रतिशत अग्रिम पेशगी अदा करनी होगी तथा संबंधित ईरानी बैंक को एक्जिम बैंक द्वारा 85 प्रतिशत के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा 7 बैंकों में से किसी बैंक द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है, नामतः बैंक मेल्लत, बैंक मेल्ली ईरान, बैंक सेपा, बैंक सदरात ईरान, बैंक तेज़ारत, बैंक ऑफ इंडस्ट्री एण्ड माइन तथा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ ईरान, ऋण की अवधि 8 वर्षों की होगी।

ईरान में भारत का निर्यात 2000-01 में 222 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 13.5% बढ़कर 2001-02 में 252 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। बिजली, रेलवे, बंदरगाह, हाइड्रो कार्बन, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में भारतीय उपस्करों एवं प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए अनेक भारतीय कंपनियाँ अपने ईरानी प्रतिपक्षों से मोलतोल करने में लगी है। एक्जिम बैंक द्वारा ईरान को मध्यावधि ऋण-व्यवस्था स्थापित करने से ईरान में भारत के निर्यातों को मात्रात्मक उछाल मिलने की आशा है।

एक्जिम बैंक ने श्रीलंका को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण-व्यवस्था उपलब्ध करायी है

श्रीलंका में भारतीय निर्यातों को समर्थन देने लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) एवं हट्टन नैशनल बैंक (एच एन बी) लि. श्रीलंका ने 12 फरवरी, 2003 को मुंबई में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण-व्यवस्था के करार पर हस्ताक्षर किये। ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत श्रीलंका के आयातक संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत अग्रिम अदायगी करेंगे तथा संविदा मूल्य के 90% क लिए एक्जिम बैंक द्वारा एच एन बी को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। एक्जिम बैंक माल के लदान पर भारतीय निर्यातकों को प्रतिपूर्ति करेगा। ऋण की अवधि 5 वर्षों की होगी।

1988 में स्थापित एच एन बी श्रीलंका का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है जिसकी कुल आस्ति 1 बिलियन डॉलर से अधिक है। बैंक अपने सहायकों एवं सहयोजित कंपनियों के साथ मिलकर अनेक तरह के वित्तीय उत्पादों एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है जिनमें शामिल है सामान्य बैंकिंग, विकास वित्तपोषण, गिरवी वित्तपोषण, पट्टे का वित्तपोषण, निवेश बैंकिंग, निगमित बैंकिंग सरकारी प्रतिभूतियों में व्यवहार करने वाली, स्टॉक बैंकिंग, बीमा सेवाएं एवं क्रेडिट कार्ड सुविधाएं।

वर्ष 2001-02 में श्रीलंका में भारत का निर्यात 630.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। संभावित क्षेत्र जिन पर भारतीय निर्यातक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं वे हैं वाहन, बिजली की मशीनें एवं उपस्कर, उपभोक्ता वस्तुएं, शक्कर, गेहूँ, पशु मूल के खाद्य उत्पाद, अनाज, स्टंपल फाइबर, मरीन उत्पाद, कपड़े एवं हीरे जवाहरात। श्रीलंका में वस्त्र, सिरामिक्स, हीरे जवाहरात, इलेक्ट्रॉनिक्स, सू प्रौ, रबर, चाय, नारियल, बागवानी एवं मरीन उत्पादों जैसे क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने की भी अच्छी संभावना है।

एक्जिम बैंक ने फिलीपीन्स को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण-व्यवस्था उपलब्ध करायी

फिलीपीन्स में भारत के निर्यात को समर्थन देने के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) एवं फिलीपीन्स व्यापार एवं निवेश विकास निगम ने एक्जिम बैंक से टिडकार्य के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण-व्यवस्था के करार पर 7 मार्च, 2003 को मनीला में हस्ताक्षर किया।

ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत फिलीपीन्स में आधारित आयातकों को संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत अग्रिम अदायगी करनी होगी तथा संविदा के 90 प्रतिशत मूल्य के लिए एक्जिम बैंक द्वारा टिडकार्य को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। माल के लदान के बाद एक्जिम बैंक भारतीय निर्यातकों प्रतिपूर्ति करेगा। ऋण की अवधि 5 वर्ष होगी। टिडकार्य जिसे फिल एक्जिम भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जनवरी 1977 में हुई थी तथा यह पूर्णतया सरकारी स्वामित्व का, वित्त विभाग, फिलीपीन्स सरकार से संबद्ध है। टिडकार्य का निगमित उद्देश्य राष्ट्रीय निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में फिलीपीन्स के आर्थिक विकास में सहयोग करना है तथा संपूर्ण एक्जिम बैंक के रूप में उभरना इसका लक्ष्य है।

फिलीपीन्स में भारत का निर्यात 2001-02 में 248 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। संभावित क्षेत्र जिन पर भारतीय निर्यातक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं वे हैं मशीनें एवं उपस्कर, परिवहन उपस्कर, खनिज ईंधन, रसायन, धातुओं के निर्माण, लोहे एवं इस्पात के निर्माण, अनाज एवं उससे बने सामान एवं अयस्क, धातु मल एवं भस्म।

हर तरह की ऋण-व्यवस्थाओं के लिए विस्तृत जानकारी हेतु कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें -

श्री पी आर दलाल

महाप्रबंधक

टेलीफोन (022) 22185272 विस्तार 2112

फैक्स (022) 22182460

ई-मेल : prdalal@eximbankindia.com

भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन

मूल रूप से पारिस्थितिकी पर्यटन का आशय है किसी स्थान की यात्रा के दौरान यथासंभव पर्यावरण प्रभाव को कम करना एवं स्वदेशी जनसमूह धारित करना जिससे वन्य जीवों एवं प्राकृतिक वास की रक्षा हो सके। यह पर्यटन, विकास का उत्तरदायी स्वरूप है जो जीवन के प्रत्येक पहलू में प्राकृतिक उत्पादों में वापसी को प्रोत्साहित करता है। यह धारणीय पारिस्थितिकी विकास के लिए भी प्रमुख है। पारिस्थितिकी पर्यटन हेक्टर सेवालस-लस्कूरियन एक मेक्सिन पर्यावरणविद द्वारा 1983 में शुरू किया गया तथा शुरू में शिक्षा पर बल देने के साथ अपेक्षाकृत शांत क्षेत्रों की प्रकृति आधारित यात्रा वर्णित करता है। तथापि यह परिकल्पना धारणीय पर्यटन उत्पादों एवं गतिविधियों की योजना, प्रबंधन एवं विकास के लिए वैज्ञानिक तरीके में विकसित किया गया। संक्षेप में पारिस्थितिकी पर्यटन की पर्यटन कार्यक्रम के रूप में परिकल्पना की जा सकती है जो प्रकृति आधारित हो, धारणीय हो, स्थानीय लोगों के लिए लाभप्रद हो, तथा शिक्षा एवं व्याख्या के रूप में प्रमुख घटक रखता हो।

अलग पर्यटन उत्पाद के रूप में पारिस्थितिकी

रीका, ब्राज़ील, बेलिज, आस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे देशों ने पारिस्थितिकी पर्यटन के गंतव्यों

को विकसित किया एवं स्पष्ट नीति दिशा निदेश एवं रणनीतियाँ बनायीं। पारिस्थितिकी पर्यटन विकास के संबंध में विशेषतया कोस्टा रीका, बेलिज जैसे देशों में अनेक अध्ययन किए गए। इन अध्ययनों में पारिस्थितिकी पर्यटन के समग्र पर्यटन में बदलते के अनेक उदाहरण लाए गए और अध्ययन के रूप में इनका अनुभव किया गया। इस समय पारिस्थितिकी पर्यटन अनेक क्षेत्रों में विकास के विभिन्न चरणों में हैं। एशिया में पारिस्थितिकी पर्यटन विकास के चरणों में व्यापक अग्रगण्य है एवं विभिन्न देशों में इसकी अलग संकल्पना है। अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा एवं विशाल वादियों से भारत को भूमण्डल के जैविक रूप से सबसे स

बृद्ध देशों के रूप में मान्यता प्राप्त है जो पारिस्थितिकी पर्यटन का अनूठा पारिस्थितिकी वविधता उपलब्ध कराता है। पारिस्थितिकी पर्यटन के अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य सिद्धांतों के अंतर्गत भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के नीतिगत समर्थन से पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल भी विकसित किए जा रहे हैं। पारिस्थितिकी पर्यटन के बारे में मीडिया, सेमिनार एवं कार्यशालाओं के माध्यम से विस्तृत जागरूकता दी जा रही है। हाल ही में पर्यटन एवं मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध में घोषित किया है कि राष्ट्रीय पार्कों, वन्य उद्यानों एवं दूसरे जंगलों में पारिस्थितिकी पर्यटन विकास के लिए प्रणोद क्षेत्र हो सकते हैं। 1998 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने पारिस्थितिकी पर्यटन सिद्धांत एवं दिशानिर्देश प्रकाशित

किया है। इसमें पारिस्थितिकी पर्यटन संसाधनों, पारिस्थितिकी पर्यटन की योजना, स्टिकधारकों की भूमिका जैसे सरकार, यात्रा प्रचारक, स्थानीय सामुदायिक पर्यटकों की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की गई है। पारिस्थितिकी पर्यटन कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ट्रेकिंग उपस्करों की खरीद, कैम्पिंग उपस्करों की खरीद में राज्य सरकारों को समर्थन देती है तथा ऊज

पुनर्निर्माण संसाधनों की परियोजनाओं में मदद करती है। राज्य सरकारें विभिन्न पर्यटन संबंधी व्यापारिक निकायों के साथ लगातार संपर्क में हैं जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन महीनों में उनकी सहायता करते हैं। अधिकांशतः पारिस्थितिकी पर्यटन सरकार के पास हैं तथा पारियोजनाए सरकार एवं निजी क्षेत्र के समर्थन से विकसित की जाती हैं। इसमें आवास एवं यात्रा प्रचलन के संचालन की आशा की जाती है। संपूर्ण भारत के कुछ प्रमुख पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल निम्न हैं, सुंदरवन (पश्चिम बंगाल), टिंजाला वन्य जीवन उद्यान (त्रिपुरा), युमथांग (सिक्किम), प्लेग पैराडिसो समुद्रतट (पाण्डिचेरी), लोहतक झील (मणिपुर), कल्चेनी एक्वा मरीन समुद्र का मिश्रण, नारियल के पट्टे एवं कोरल रीफ (लक्षद्वीप), गिरराष्ट्रीय उद्यान (गुजरात), कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) थेनमाला राष्ट्रीय उद्यान (केरल), एवं चिल्का झील (उड़ीसा)। एन्रिजम बैंक के डेस्क कैलकुलेशन 2003 में माल के ऐसे सुंदर पारिस्थितिकी पर्यटन स्थलों का वर्णन किया गया है। इस समय संरक्षण के "हरित नियम" लोगों को जागरूक बना रहे हैं कि मानव एवं पर्यावरण

संरक्षित रह सकते हैं। पर्यटन के आर्थिक, पर्यावरण एवं सामाजिक लाभों को अधिकतम बनाइए। इसका एकमात्र रास्ता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति स्टिकधारक है। हमें अपनी पिछली कमियों को दूर करने एवं प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने की आवश्यकता है। भारत में भी इस आंदोलन को गति मिल रही है। अधिक से अधिक पर्यटन एवं पर्यटन से संतुष्ट संगठन पारिस्थितिकी पर्यटन की आवश्यकता को संबोधित कर रहे हैं एवं देश में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 को अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिकी वर्ष के रूप में मनाया है। इस समय अधिक उत्तरदायी पर्यटन विश्व को इसकी पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित क

एक्जिमिअस केन्द्र स्तम्भ

वर्ष 2003 की पहली तिमाही में केन्द्र ने निम्न कार्यक्रम आयोजित किए - सरल निर्यात - निर्यात वित्तपोषण एवं जोखिम को करने पर एक सेमिनार एक्जिम बैंक एवं ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्राइवेट लि (जी टी एफ) द्वारा संयुक्त रूप से पहला कार्यक्रम किया गया। श्री जेरोन कोन्स्टाम फैक्टर्स चैन इंटरनेशनल, एम्सटर्डम के महासचिव ने प्रमुख संबोधन किया।

दूसरा कार्यक्रम सॉफ्टवेयर गुणवत्ता सी एम एम मानक पर केन्द्र में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिस में श्री के. के. रमन, सह निदेशक और श्री डी. शंकररामन, प्रबंधक के पी एम जी, बैंगलूर, संकाय सदस्य थे। “तीसरा कार्यक्रम कृषि उद्यमों का मूल्य जोखिम नियंत्रण एवं प्रतिभूतिकरण” पर केन्द्र में एक कार्यशाला आयोजित की गई। भारतीय पौधरोपण प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर डॉ. दामोदरन ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

चौथा कार्यक्रम विकसित देशों के बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली एवं इंजीनियरी उत्पादों के लिए प्रमाणन एवं मार्किंग अपेक्षाओं पर केन्द्र में, एक कार्यशाला आयोजित की गई। श्री वी रमेश, कन्फर्मिटी असेसमेंट सर्विस के समूह नेता ने कार्यशाला को संबोधित किया।

पाँचवां कार्यक्रम कनाडा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्थिति एवं भारतीय कंपनियों के लिए इसके अवसर पर केन्द्र में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को निम्न ने संबोधित किया - श्री कीथ पार्सेनेज, महानिदेशक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शाखा उद्योग, कनाडा, श्री पीटर नेस्विट, प्रबंधक, स्कोटिया बैंक श्री डाग पैटर्सन, क्रांडसल एवं वरिष्ठ व्यापार आयुक्त। कनाडा उच्चायोग, मुंबई, श्री जुल्फी सादिक, वाणिज्यिक कौंसलर, कनाडा उच्चायोग, नई दिल्ली एवं श्री डी. पी. विट्टल, व्यापार सलाहकार, कनाडा व्यापार कार्यक्रम बैंगलोर।

छठवां कार्यक्रम मध्य/पूर्व यूरोप एवं सी आइ एस देशों में नए व्यवसाय अवसर विकसित करना भारत एवं ई बी आर डी की भागीदारी पर एक्जिम

बैंक एवं यूरोपीयन बैंक फार रीकंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट द्वारा मुंबई में संयुक्त रूप से कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को निम्न ने संबोधित किया - श्री टी. सी. वेंकट सुब्रमण्यन, प्रबंध निदेशक, एक्जिम बैंक, श्री ब्रुनो बाल्वानेरा, प्रमुख, व्यवसाय विकास एवं श्री जार्जो ओर्लोव, प्रमुख बैंकर, ई बी आर डी इसी तरह की एक कार्यशाला नई दिल्ली में भी आयोजित की गई। कार्यशाला को श्री ब्रुनो बाल्वानेरा, प्रमुख, व्यवसाय विकास एवं सुश्री नंदिता प्रसाद वरिष्ठ बैंकर, ई बी आर डी ने संबोधित किया।

सूक्ष्म एवं विशेष रसायनों के लिए निर्यात विपणन एवं स्रोतकरण कार्यक्रम पर विकासशील देशों से आयात संवर्धन केन्द्र के साथ एक्जिम बैंक ने मुंबई में एक ज्ञानवर्धक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला को एक्जिम बैंक के प्रबंध निदेशक श्री टी सी वेंकटसुब्रमण्यन ने संबोधित किया। इसी तरह एक कार्यशाला अहमदाबाद में आयोजित की गई जिसे श्री के. शामजी, उपनिदेशक लघु उद्योग सेवा संस्थान लघु उद्योग मंत्रालय, अहमदाबाद ने संबोधित किया।

“ भारतीय उद्योग पर विश्व व्यापार संगठन की उलझन ” पर केन्द्र में कार्यशाला की गई। कार्यशाला को श्री आर श्रीनिवासन, सलाहकार आर्थिक प्रखण्ड, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली ने संबोधित किया।

अगली तिमाही के कार्यशाला सेमिनार के कार्यक्रम निम्न हैं -

- 1) बौद्धिक संपत्ति नियम 2) भारत से कपड़ा निर्यात रणनीति 3) खाद्य सुरक्षा एवं नए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक
- 4) एक समुद्रपारीय इंटीटी स्थापित करने के लिए कर रणनीतियाँ
- 5) आस्ट्रेलिया में भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन
- 6) यूरोप में सू प्रौ क्षेत्र के संवर्धन की संभावना।

केन्द्र अपनी भावी कार्यसूची पर सुझावों का स्वागत करता है।

पुस्तक समीक्षा

ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिस्कटेन्ट्स : जोसेफ स्टिगलिट्ज

अपनी पुस्तक में जोसेफ स्टिगलिट्ज ने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से कार्य करने वाले पश्चिमी जगत ने निजीकरण, उदारीकरण एवं स्थिरीकरण को अव्यवस्थित कर दिया है तथा इसकी सलाह मान कर तीसरी दुनिया के अनेक देश एवं पहले के साम्यवादी देश पहले की तुलना में अब अधिक बेहाल हो गए हैं। विश्व बैंक के भूतपूर्व मुख्य अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रपति क्लिंटन की आर्थिक सलाहकार परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष का इस तरह का वक्तव्य आश्चर्यजनक एवं चुनौतीपूर्ण है।

स्टिगलिट्स का कहना है कि विकासशील देशों पर वैश्वीकरण का बुरा असर है, विशेषतया उन देशों के गरीबों पर इसका और भी बुरा असर है। उनका विश्वास है कि वैश्वीकरण मुक्त व्यापार से बाधाओं को हटाना एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का निकट एकीकरण अच्छाई के लिए एक बल हो सकता है तथा इसके पास विश्व में सभी को समृद्ध करने की सामर्थ्य है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से वैश्वीकरण किया जा रहा है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

प्रजातांत्रिक सरकारों को वैश्वीकरण की गति निश्चित करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। वैश्विक राजधानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों द्वारा उनसे यह नहीं कहा जाना चाहिए कि क्या करना है। पुस्तक में प्रमुख तर्क यह है कि वैश्वीकरण के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए एक प्रबंधित प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें प्रजातांत्रिक सरकारें अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष या वैश्विक पूंजी बाजारों की तुलना में अधिक शक्ति का प्रयोग करती हैं।

श्री लंका

2001 में सेवा क्षेत्र के फिर से उत्कर्ष के कारण 1.4% की ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में श्री लंका



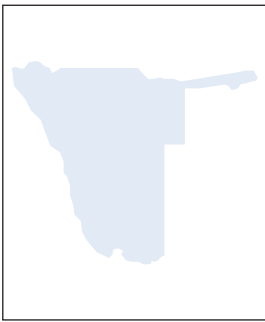
की अर्थव्यवस्था 2002 में 3.2% बढ़ी। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का वर्चस्व है जो 2001 में राष्ट्र के सकल देशी उत्पाद का 52.4 था। दिसंबर

2002 में श्री लंका टेलीकॉम में सरकार की 12% शेयर धारिता की सफलपूर्वक ब्रिकी से निजीकरण कार्यक्रम में तेजी आई। सरकार अपनी विशाल व्यापारिक कंपनी कोऑपरेटिव होलसेल इस्टैब्लिसमेंट के विनिवेश पर भी विचार कर रही है। यह कंपनी देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं, कृषि उपज एवं अन्य उपभोक्ता सामानों का आयात एवं विपणन करती है। एशियाई विकास बैंक ने कोलंबो पत्तन की संवर्धित कुशलता एवं विस्तार उत्तरपूर्व सामुदायिक पुनःस्थापन एवं विकास, दक्षिणी प्रांत को ग्रामीण आर्थिक उन्नति एवं एस एम ई क्षेत्र कार्यक्रम के विकास के लिए 4 परियोजनाओं हेतु 2001 में 146 मिलियन अ.डॉ. के 6 ऋण अनुमोदित किए। एशियाई विकास बैंक ने 4.1 मिलियन अ.डॉ. के 9 तकनीकी सहायता अनुदान अनुमोदित किये हैं। आर्थिक सुधार के उद्देश्य से दिसंबर 2002 में विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित श्री लंका ने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त किया।

नामीबिया

2001 में खान एवं उत्खनन उद्योग स. दे. उ. के 14.3% के लिए उत्तरदायी है। हीरा नामीबिया का प्रमुख निर्यात है जो इसके आधे से अधिक निर्यातों के लिए उत्तरदायी है।

नामीबिया मिनरल्स कार्पोरेशन (नाम्को) द्वारा समुद्र तट की वृद्धि से नामाबिया में हीरे के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई



है। विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय विकास संघ से रियायती ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से नामीबिया सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी में वर्गीकृत होना चाहता है। नामीबिया को 2001-02 कवर करते हुए राष्ट्रीय संकेतक कार्यक्रम के अंतर्गत यूरोपीय संघ से सहायता का प्रवाह जारी रहेगा जो नौवें यूरोपीय विकास निधि से 88 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का संवितरण उपलब्ध कराता है। इस समय विश्व बैंक नामीबिया में गरीबी उन्मूलन एवं एच आई वी / एड्स संबोधित करने, स्थानीय क्षमता के निर्माण एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के संवर्धन के लिए सरकारी प्रयासों के समर्थन हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने पर कोई ऋण नहीं है। नामीबिया के लिए आइ एफ सी कुल 11 मिलियन अ.डॉ. की बचनबद्धता है।

पोलैण्ड

पोलैण्ड ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बांड के साथ ब्रिटिश बाज़ार में पहला यूरो बांड शुरू किया है। 2002 में शुद्ध पोर्टफोलियो निवेश में उत्कर्ष था, जिसकी वजह से अमेरिकी बाज़ार में 10 वर्ष के यूरो बांड का 1 बिलियन का सफल निर्गम देखा

गया। अवनमित आर्थिक स्थिति एवं निजीकरण की धीमी गति के कारण एफ डी आई की मंदी जारी थी। यद्यपि यूरोपीय संघ में व्यापार

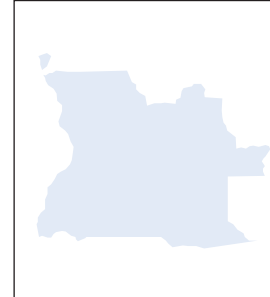


समायोजन हो चुका है, भू सं की संपूर्ण सदस्यता कृषि एवं खाद्य पदार्थों में व्यापार करेगी। भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी सुविधा के लिए पोलैण्ड के यू सं के ढांचागत निधि में पहुँच द्वारा निवेश एवं व्यापार दोनों में बढ़ोतरी होगी। 1990 से इंटरनैशनल बैंक, फॉर रीकंस्ट्रक्शन एण्ड डिवेलपमेंट ने 37 परिचालनों के लिए 5.4 बिलियन अ.डॉ. लगाया है।

अंगोला

अर्थव्यवस्था में तेल क्षेत्र का वर्चस्व है। खनन, सेवा, कृषि एवं निर्माण भी प्रमुख हैं। तेल के उत्पादन से 2003 में स.दे.उ. को वास्तविक दर 6% एवं 2004 में 6.2% तक विस्तार प्रत्यक्ष रूप बढ़ने की आशा है क्योंकि आर्थिक से तेल उत्पादन पर निर्भर है। अफ्रीका तेल नीति अभिक्रम समूह

ने अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा में रणनीतिक महत्व पाने के लिए अंगोला को नोट किया है। अंगोला को दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (द.अ.वि.स.) की अध्यक्षता ली है। अंगोला को 350 मिलियन



अ.डॉ. की परियोजना के लिए विश्व बैंक से आशा है। इस समय अंगोला में विश्व बैंक की दो परियोजनाएं हैं, एक 5 मिलियन अ.डॉ. की संघर्ष

के बाद की रिकवरी लर्निंग एण्ड इन्वोवेशन लोन एवं सामाजिक कार्रवाई निधि को समर्थन देने वाली 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समर्थन। देश में युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के कारण नई बुनियादी सुविधाओं की संविदाएं उभर रही हैं तथा सड़क एवं रेल नेटवर्क को प्राथमिकताएं ही गई हैं। शांति स्थापना के बाद अनेक हाइड्रोइलोकट्रिक परियोजनाओं की प्रगति हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने देश के पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा की है संकल्प किया है कि माइन की सफाई एवं मानव सहायता सर्वोत्तम प्राथमिकताएं हैं लेकिन गैर तेल एवं हीरा क्षेत्र लंबी एवं कठिन प्रक्रिया है।

फिलीपीन्स

सेवाक्षेत्र का फिलीपीन्स कर अर्थव्यवस्था में वर्चस्व है। विशेष उद्देश्य आस्ति वाहन (वि ड आ वा) विधेयक अनुमोदित किया गया, जिससे अशोध्य ऋण आस्ति प्रबंधन कंपनियों में स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी तथा व्यापक आस्तियों के विमोचन द्वारा जिनमें क्रेता इच्छुक हों फिलीपीन्स में निवेश प्रोत्साहित करेगी। 2001 में एशियाई विकास बैंक ने मिन्डानाओ बुनियादी शहरी सेवा क्षेत्र एवं गैर बैंक वित्तीय



नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कुल 105 मिलियन अ.डॉ. का ऋण अनुमोदित किया। 2001 में 7.6 मिलियन अ.डॉ. के 9 तकनीकी सहायता अनुदान अनुमोदित किए गए थे। 1957 से विश्व बैंक ने फिलीपीन्स को 2.18 ऋण 9 क्रेडिट मंजूर किया है जो 11.5 बिलियन अ.डॉ. से अधिक है।

चयनित मुद्राएं

मेक्सिको

मेक्सिको की मुद्रा पेसो स्वतंत्र रूप से प्रवाही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विनिमय दर बाज़ार द्वारा निर्धारित होती है तथा हस्तक्षेप का उद्देश्य उतार-चढ़ाव को हल्का करने एवं उतार-चढ़ाव को कम करना होता है। 1 अगस्त 1996 से बैंको डि मेक्सिको केन्द्रीय बैंक ने प्रवाही विनिमय दर नीति के प्रति अपनी वचनबद्धता को बिना समाप्त किए बाज़ार में विदेशी मुद्रा खरीदने की प्रणाली शुरू की इस प्रणाली के अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक ने विकल्प की मासिक बोली आयोजित की जो वित्तीय संस्थानों को एम एक्स एन के विरुद्ध इसे अमेरिकी डॉलर बेचने का अधिकार देता है। नवंबर 1991 से जुलाई 1996 के बीच एक लचीला विनिमय प्रशासन अपनाया गया जिसके अंतर्गत पेसो एक हस्तक्षेप बैंक के भीतर उतरा-चढ़ा। एम एक्स एन की विनिमय दर 1995 में 7.6825 के औसत से, 1998 में 9.8650 एवं 2001 में 9.1423 की औसत दर से उतरा चढ़ा जिसने 7 वर्षों में अमेरिकी डॉलर के विरुद्ध 1.9% का मूल्य ह्रास दर्ज किया। वर्ष 2002 के दौरान एम एक्स एन अप्रैल में 9.31 से 9% दिसंबर में 10.15 तक कम हुआ। मेक्सिको का विदेशी मुद्रा भण्डार 1995 में 16.84 बिलियन अ.डॉ. से बढ़कर 2001 में 44.74 अमेरिकी डॉलर हो गया तथा नवंबर 2002 में 46.77 बिलियन अ.डॉ. हो गया। 1995 में इसका 7 बिलियन अ.डॉ. का अनुकूल व्यापार संतुलन था जो धीरे-धीरे घटकर 1998 में -7.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर एवं

2001 में -9.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया कुल विदेशी निवेश 1997 में 17.86 बिलियन अ.डॉ. से 2001 में 27.77 बिलियन अ.डॉ. बढ़ गया जो मेक्सिको का आर्थिक सुधार दर्शाता है। मेक्सिको का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार एवं निवेश भागीदार अमेरिका है जो लगभग 89% निर्यात एवं 68% आयात करता है तथा विनिमय दर संचलन अमेरिका में हुई घटनाओं से प्रभावित होता है। 24 मार्च, 2003 को एम एक्स एन 10.78 प्रति अमेरिकी डॉलर उद्धृत किया गया एवं इस वर्ष उसी स्तर पर घूमता रहा।

पोलैण्ड

अप्रैल 2000 से पोलैण्ड की मुद्रा ज्लाटी को स्वतंत्र रूप से प्रवाही होने की स्वीकृति है। 1991-2000 के बीच नैशनल बैंक ऑफ पोलैण्ड ने जो सेंट्रल बैंक है (+/-) 15% के बैंड के भीतर लचीली क्रांति प्रणाली अपनाया है। 1990 में आर्थिक संक्रमण शुरू हुआ एवं तब तक पोलैण्ड ने अमेरिकी डॉलर के विरुद्ध स्थिर विनिमय दर प्रणाली अपनायी थी। 1992 के दौरान पी एल एन प्रति अमेरिकी डॉलर 1.36 उद्धृत किया गया। 1 जनवरी, 1995 को ज्लाटी का पहले के ज्लाटी के 10,000 के बराबर हो गया। विनिमय दर 1995 में 2.47 पी एल एन से 1998 में 3.52 हो गया, 2002 में 4.143 एवं 2002 में 4.15 हो गया जो पिछले 7 वर्षों में मूल्य ह्रास दर्शाता है तथा 9.72% की वार्षिक दर से ह्रास दर्शाता है। पोलैण्ड के सकल देशी उत्पाद में 2002 में 1.3% की दर से औसत वार्षिक वृद्धि हुई है। अनुमान है कि अर्थव्यवस्था का 2003 में 2% से अधिक बढ़ना जारी रहेगा। 2002 में मुद्रा स्फीति की दर 1.90% थी तथा इसके 2% पर स्थिर रहने का अनुमान था। विदेशी मुद्रा भण्डार जनवरी 2002 में 26.05 बिलियन अ.डॉ. से जनवरी 2003 में 30.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया। उपयुक्त अनुकूल संकेतकों के साथ ज्लाटी अमेरिकी डॉलर के विरुद्ध स्थिर रहा। 24 मार्च, 2003 को पी एल एन को 4.0565 उद्धृत किया गया एवं इस वर्ष रेंज वाइड होने की आशा थी।

श्री लंका

श्री लंका की मुद्रा रुपया है (एल के आर) 24 अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के पिटारे के विरुद्ध एल के आर को दैनिक आधार पर मूल्यांकित किया

जाता है तथा श्री लंका के सेन्ट्रल बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक के मध्य दर पर निर्धारित किया जाता है। 20 जून, 2000 को 18 महीनों में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतरराष्ट्रीय भण्डार के कम होने एवं बाज़ार में नकदी की कमी के कारण केन्द्रीय बैंक ने अमेरिकी डॉलर के विरुद्ध रुपए में 6 प्रतिशत की कमी की। विदेशी विनिमय क्रय दर 75.60 एल के आर एवं विक्री दर 79.67 एल के आर पर घोषित की गई। उदारीकरण प्रक्रिया के अनुरूप सरकारी भण्डार में सतत कमी के कारण एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश के समर्थन को संघटित करने के लिए सरकार ने 23 जनवरी, 2001 को प्रवाही विनिमय दर प्रशासन अपनाया। अंतरराष्ट्रीय कोष के ऋण से 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आहरण भण्डार स्तर को अनुरक्षित करने में सहायक हुआ। दो दिनों के भीतर एल के आर अमेरिकी डॉलर के विरुद्ध 85 से 99 के आसपास चढ़ गया जो लगभग 17% का मूल्यह्रास दर्शाता है। यद्यपि सेन्ट्रल बैंक क हस्तक्षेप से एल के आर की स्थिरता लगभग 90 के स्तर पर पुनर्स्थापित की गई। सोने को छोड़कर विदेशी मुद्रा भंडार 1995 में 20.88 बिलियन से घटकर 1998 में 19.80 वि अमेरिकी डॉलर, 2000 में 10.39 बिलियन अ.डॉ. से बढ़कर 2002 में 14.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले 5 वर्षों में अमेरिकी डॉलर की तुलना में एल के आर वर्षानुवर्ष आधार पर 1998 में 64.45 से 2002 में 95.66 हो गया। अप्रैल 2002 में 96 एल के आर: 1 अ.डॉ. के वैरियर को तोड़ने से श्री लंका का रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहा। अटकलबाजी का दबाव न होने के कारण एवं सरकार द्वारा प्रतिबंधित उधारी के कारण मुद्रा पर दबाव कम करने में मदद मिली है। 2002 में 6.6% के वार्षिक औसत से एल के आर में ह्रास हुआ है। श्री लंका का स.दे.उ. वर्षानुवर्ष आधार पर लगभग 3.2% की दर से बढ़ा है तथा ऐसा अनुमान है कि 2003 में यह 5.5% को पार कर जाएगा। शांति बहाली एवं उदारीकरण उपायों से निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ने की आशा है। 2002 में मुद्रास्फीति 93.6% थी तथा 2003 में इसके 8% तक गिरने की आशा है। 24 मार्च, 2003 को के आर 96.92 प्रति अमेरिकी डॉलर उद्धृत किया गया एवं इस वर्ष में इसके और कम होने की आशा है।

कैंकन मेक्सिको के लिए मार्ग - 5 वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन

विश्व व्यापार संगठन का पाँचवा मंत्री स्तरीय सम्मेलन 10 से 14 सितम्बर 2003 को कैंकन मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्य दोहा विकास कार्यसूची के अंतर्गत बातचीत में हुई प्रगति का जायजा लेना है। दोहा क्रतार में नवंबर 2001 में चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हुई घोषणा से वर्तमान करार के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों सहित अनेक विषयों एवं अन्य कार्य पर बातचीत के लिए अवसर उपलब्ध कराया है। चर्चा में कृषि एवं सेवा सहित अनेक मद शामिल थे जो 2000 के आरम्भ में शुरू हुए थे। अन्य अनेक मुद्दों को अब शामिल किया गया है। घोषणा में 1 जनवरी 2005 तक सभी मुद्दों पर बातचीत पूरी करने के लिए निश्चित किया गया है। मई 2003 में विवाद समझौते पर बातचीत समाप्त होनी है तथा कैंकन मंत्री स्तरीय सम्मेलन में प्रगति की समीक्षा की जानी है।

विकासशील विश्व के स्वाभाविक नेता के रूप में विश्व व्यापार संगठन जैसे स्तर पर भारत अपनी भीनी-भीनी सुगन्ध बनाए रखे हुए प्रतीत होता है, विशेषतया अफ्रीका में छोटे राष्ट्र जटिल विश्व व्यापार संगठन की बातचीत के लिए बुनियादी सुविधा न रखने से भारत पर समर्थन के

लिए अभी भी विश्वास करते हैं। जिम्बाब्वे, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया एवं मोरक्को सहित एक दर्जन से अधिक अफ्रीकी देशों ने यह विचार व्यक्त किया है कि उन्नत देशों से कृषि मदों की बाढ़ के संबंध में सामान्य रणनीति बनाने में जो उनकी घरेलू कृषि के लिए खतरा है भारत को कृषि पर विश्व व्यापार संगठन की सभी बातचीत में नेतृत्व करना चाहिए पिछले दो मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में सैद्धांतिक स्टैण्ड लेने एवं इस पर बने रहने से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तथा भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को अन्य विकासशील देशों से कैंकन में बातचीत के तरीके को और अधिक कारगर बनाने के लिए द्विपक्षीय बातचीत के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

फरवरी 2003 में टोक्यो में विश्व व्यापार संगठन का एक छोटा मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ ताकि विश्व व्यापार संगठन के दोहा विकास कार्यसूची के लिए अंतरराष्ट्रीय पारस्परिक समझ विकसित की जा सके, एवं विशेषतया कैंकन में मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ऐसा हो सके। छोटे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अत्यधिक महत्त्व था क्योंकि इसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, चीन एवं कैरन समूह के सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया। विकसित एवं विकासशील देशों के लिए प्रमुख मुद्दों पर पकड़ बनाए रखने एवं यथा संभव दृढ़ता पूर्वक अपनी स्थिति रखने के लिए एक अवसर था चूंकि विश्व व्यापार संगठन पूरी तरह से बातचीत के लिए है विभिन्न ब्लाक एवं समूह इसकी पहचान कर सके कि कौन से प्रमुख खिलाड़ी उन्हें समर्थन दे सकते हैं या उनका विरोध कर सकते हैं जो दोहा विकास कार्यसूची में वर्णित किया गया है।

सम्मेलन में भारत का ध्यान कृषि, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकार, स्वास्थ्य एवं इसकी कार्य-सूची में कृषि एवं गैर कृषि उत्पादों एवं सेवाओं को कवर करते हुए बाज़ार पहुँच संबंधी मुद्दें शामिल थे। सिंगापुर के चार मुद्दे थे (जैसे निवेश, प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक खरीद में व्यापार सुविधा एवं पारदर्शिता), विकास संबंधी मुद्दें, कैंकन के लिए नियम एवं सामान्य चर्चा

शामिल थे। भारत ने विकसित देशों विशेषतया अमेरिका एवं यूरोपीय संघ को स्पष्ट कर दिया कि कैंकन के विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन में बाधाओं को हटाना पूर्णतया उनके ऊपर है।

विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी सदस्यों की व्यापारिक नीतियाँ आवधिक समीक्षा के अधीन है। भारत की व्यापार नीति हर चार वर्ष पर समीक्षा के अधीन है तथा जून 2002 में इसकी तीसरी समीक्षा में भारत की इसकी सुधार प्रक्रिया के लिए सराहना की गई। भारत में व्यापार नीति एवं चलन पर विश्व व्यापार संगठन के सचिवालय की रिपोर्ट में यह जोर दिया गया है कि भारत के प्रयासों को भारत के व्यापारिक भागीदारों की ओर से भारत के निर्यातों की बाधाओं को यदि समाप्त नहीं किया जा सकता तो कम करने के लिए विशेषतया दोहा कार्य कार्यक्रम में सतत चर्चा के विशेष संदर्भ में अत्यधिक बढ़ाया जा सकता है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन एवं दोहा विकास कार्यसूची के लिए अपना समर्थन बार-बार दोहराया है लेकिन विचार करता है कि यदि आगे प्रगति करनी है तो दोहा में किए गए वायदों को पूरा करने की जिम्मेदारी विकसित देशों पर होगी। इस विचार को अनेक सदस्यों ने पृष्ठांकित किया है जो इस बातचीत में भारत का प्रतिनिधित्व चाहते हैं।

इसमें प्रकाशित समाचार और जानकारी विभिन्न ऐसे स्रोत /माध्यमों से एकत्रित की गयी है जो कि अपने आप में प्रामाणिक हैं। प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता को बनाए रखने में पूरी सावधानी बरती गयी है फिर भी इस प्रकार की जानकारी की प्रामाणिकता और यथार्थता की कोई जिम्मेदारी एक्सिम बैंक की नहीं है।

नोट : भारतीय रुपये का उल्लेख करोड़ और लाख में किया गया है -

1 करोड़ : 10 मिलियन
1 लाख : 100 हजार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक, केंद्र एक भवन,
21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.
दूरभाष : 2218 5272 फ़ैक्स : 2218 2572
ई-मेल : eximcord@vsnl.com